



न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 32/2014



- 1 रामूराम उर्फ रामलाल पुत्र बालुराम।
- 2 हनुमान प्रसाद पुत्र बालुराम।
- 3 अमरचन्द पुत्र बालुराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम मोहनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांत

बनाम

- 1 भागोती पत्नी प्रहलाद।
- 2 मुकेश पुत्र प्रहलाद।
- 3 राधेश्याम पुत्र प्रहलाद उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता भागोती पत्नी प्रहलाद।
- 4 प्रेमलता पुत्री प्रहलाद उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता भागोती पत्नी प्रहलाद।
- 5 सीताराम पुत्र ईशरा।
- 6 ग्यारसी बेवा मूलचन्द।
- 7 मालीराम पुत्र मूलचन्द।
- 8 विनोद कुमार पुत्र मूलचन्द।
- 9 अर्जुन पुत्र मूलचन्द।
- 10 मांगीलाल पुत्र किशना।
- 11 सीताराम पुत्र किशना।
- 12 प्रेमचन्द पुत्र बालुराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम मोहनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 13 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेंट

106  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
सीकर



अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ जिला सीकर बइजलास श्री एम.आर. बगड़िया आर.ए.एस. प्रकरण संख्या 125/2013/दावा(पुराने 184/2000) उनवानी रामूराम उर्फ रामलाल आदि बनाम सोनी आदि दावा बाबत उदघोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन दिनांकित 13.01.2004

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांत

-निर्णय-

दिनांक:-22-1-20

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 125/2013 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।


प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा एक नियमित वाद संख्या 125/13/दावा (पुराने 184/2000) रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 4 के पूर्वज प्रहलाद, सोनी बेवा ईशरा तथा रेस्पोंडेंट संख्या 5 लगायत 13 के विरुद्ध बाबत उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 के संयुक्त खाते, कब्जे व हक, अधिकार की पैतृक कृषि भूमियां खसरा नम्बर 63 रकबा 0.16 हैक्टेयर 71 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 119/599 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों के पुराने खसरा नम्बर 164 रकबा 13 बिस्वा, 165 रकबा 13 बीघा 3 बीघा 5 बिस्वा

106  
प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन सहायक अपील आधिकारी  
दांतारामगढ़



रिकार्ड में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 के पिता बालुराम उपरोक्त भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से काबिज काश्तकार रहे हैं। उनकी मृत्यु काफी वर्ष पूर्व हो गई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 उनके पुत्रगण एवं वैध उत्तधिकारीगण हैं। वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 व इनके पूर्वजों का विगत 45 वर्षों से भी अधिक समय से निरन्तर लगातार और प्रकट रूप से काबिज चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या 11 एवं वादीगण के प्रस्तुत वाद विषय वस्तु और वादग्रस्त भूमियों में समान हित निहित है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 11 यहां नहीं होने के कारण उन्हें औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में जरिये एडवर्स पजेशन खातेदार अधिकार परिपक्व एवं प्राप्त हो चुके हैं। राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की साजिश से वादीगण संख्या 1 के पिता का नाम ईशारा, वादी संख्या 2 के पिता का नाम किशना गलत रूप से अंकित कर दिया। अन्य वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 11 का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित नहीं होने दिया। उक्त स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 विगत कुछ समय से वादग्रस्त भूमियों को हड़पने की कुचेष्टा में संलग्न हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 वादग्रस्त भूमियों पर से वादीगण को बेदखल करने, पेड़ पौधे काटने, नींव सींव नष्ट भ्रष्ट करने पर आमादा है, जिनका उन्हें कोई हक, अधिकार नहीं है। उक्त परिस्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। यह दावा पेश करने पर विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के आधार पर दावा खारिज किए जाने बाबत निर्णय व डिक्री पारित किये जाने

  
प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
कार



में भारी भूल की गयी है कि वादीगण का कब्जा, काशत किस प्रकार से विवादित आराजियात पर बकाशत अतिक्रमी या अन्य प्रकार से है, साबित करने में असफल रहे हैं। जबकि इस निमित्त अपीलांट द्वारा वाद पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का पूर्वज बालु राजस्थान काशतकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज चला आ रहा था। उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 13 बहैसियत उत्तराधिकारी काबिज चले आ रहे हैं। इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को स्वामी मान्य किये जाने की स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 को जरिये प्रतिकूल कब्जा भी खातेदारी, हक अधिकार परिपक्व एवं प्राप्त हो चुके हैं। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में भारी भूल कारित की गयी है कि वाद पत्र में कुर्सीनामा या वारिसनामा भी पेश नहीं किया गया है कि वर्तमान जमाबंदी में गलत नाम अंकित हो गया एवं वास्तविक नाम रिकार्ड के अनुसार वादीगण का एवं उनके पूर्वजों का रहा है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन वाद पत्र की धारा 1 में ही इस सम्बंध में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि वादास्पद भूमि को अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 11 का पूर्वज बालु काशत करता था तथा अपीलाधीन वाद के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 उसके उत्ताधिकारीगण हैं। बालु पुत्र आशा सही नाम दर्ज होना गिरदावरी संवत् 2009 से 2016 में अंकित है, इसके अलावा अपीलांट द्वारा इस तथ्य को मौखिक साक्ष्य जिसका कोई खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं है से भी इस स्थिति को पूर्णतया साबित किया गया है कि अपीलांट रामू व हणमान का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज किया गया है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में भारी भूल कारित की गयी है कि साक्ष्य शपथ तो बताई है एवं इनके समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं उनमें वादीगण की कब्जा काशत साबित नहीं है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अपीलांट का कब्जा काशत पूर्णतया साबित था।

प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
कलकत्ता



श्री आशीष शर्मा एडवोकेट द्वारा दिनांक 30.07.2002 को वादग्रस्त भूमियों की मौका रिपोर्ट तैयार करके अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिसका विपक्षीय पार्टी द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया। उक्त मौका रिपोर्ट से अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 11 का कब्जा पूर्णतया प्रमाणित है। मौका रिपोर्ट दिनांक 30.07.2002 तथा आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय दिनांक 02.01.2012 की प्रतिलिपि अपीलांट व वकील साहब की गलती से विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी। जिसको अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस निमित्त अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी. भी प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में दिनांक 21.12.2000 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 1 जरिये वकील किशोर सिंह उपस्थित होकर वकालत नामा पेश करने का अंकन है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 01 सोनी देवी की और से दिनांक 25.01.2001 को जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद खारिज करने का कथन किया गया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में इस जवाब दावा प्रस्तुत करने के तथ्य का कोई अंकन नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद कथन एवं जवाब दावे के आधार पर कोई तनकीयात भी कायम नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।


जहां तक अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 के आवेदन के साथ निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने का प्रश्न है यह लोक दस्तावेज है अत आदेश 41 नियम 27 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

206  
प्रधान अधिकारी एवं  
पदेन राज्य अपील अधिकारी  
मेरठ



उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद कथन एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करें, उभयपक्ष के साक्ष्य लें एवं बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2020 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 22-1-20 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(राजवीर सिंह खोसला)  
मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,  
सीकर